



भारत का गज़तपत्र

The Gazette of India

प्रतापारण

EXTRAORDINARY

भाग II—संख्या 3—उपसंख्या (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

12/11/1972

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 504] नई बिल्ली, सोमवार, नवम्बर 27, 1972/अग्रहायण 6, 1894

No. 504] NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 27, 1972/AGRAHAYANA 6, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT

ORDER

New Delhi, the 27th November 1972

No. 726(E)/18FB/IDRA/72.—Whereas in exercise of the powers conferred by section 18AA of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government, by its order No. S.O. 695(E)/18AA/IDRA/72, dated the 3rd November, 1972 authorised the Industrial Reconstruction Corporation of India Limited, Calcutta (hereinafter referred to as the Authorised Controller) to take over the management of Messrs Ganesh Flour Mills Company Limited (hereinafter referred to as the said undertaking);

And whereas, the Authorised Controller has taken over the management of the said undertaking on the 4th November, 1972;

And whereas the Central Government is satisfied that it is necessary, so to do in the interests of the general public with a view to preventing fall in the volume of production of the following scheduled industries, namely vanaspati, solvent-extracted oils, processed foods and electrical fans;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 18FB of the said Act, the Central Government hereby declares that—

(a) the enactments, or portions thereof, as the case may be, specified in the Schedule to this order shall not apply to the said industrial undertaking, and

(b) the operation of all contracts, assurances of property, agreements, settlements, awards, standing orders or other instruments in force (other than those relating to secured liabilities to banks and financial institutions), to which the said undertaking is a party or which may be applicable to it immediately before the date of publication of this order in the Official Gazette, and all the rights, privileges, obligations and liabilities accruing or arising thereunder before the said date, shall remain suspended.

2. This order shall remain in force for a period of one year commencing from the date of its publication in the Official Gazette.

THE SCHEDULE

- (1) The Industrial Employment (Standing Orders) Act, 1948.
- (2) The following chapter and sections of the Industrial Disputes Act, 1947, namely:—
 - (i) Chapter V-A
 - (ii) Section 33(c)
 - (iii) Section 9(A)

[No. 4/12/72-C.U.C.]

K. S. BHATNAGAR, Jt. Secy.

श्रीधोगिक विभाग मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 27 नवम्बर, 1972

का० आ० 726 (अ) / 18 एफ बी०/आई० डी० आर० ए०/72.—यतः केन्द्रीय सरकार ने उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपने आदेश सं० का० आ० 695 (ई०) / 18ए०/आई० डी० आर० ए०/72, तारीख 3 नवम्बर, 1972 द्वारा भारत के श्रीधोगिक पुरानांठन निगम लिमिटेड, कलकत्ता (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकृत नियंत्रक कहा गया है) को मैसर्स गणेश फ्लोर मिल्स कम्पनी लिमिटेड (जिसे इसमें हस्तकेपश्चात् उक्त उपक्रम कहा गया है) का प्रबन्ध ले लेने को प्राधिकृत किया था;

श्रीर यतः प्राधिकृत नियंत्रक ने उक्त उपक्रम का प्रबन्ध 4 नवम्बर, 1972 को संभाल लिया है;

श्रीर यतः केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि निम्नलिखित अनुसूचित उद्योग में, प्रथमतु बनस्पति, विलायक निस्सारण तेल, तैयार खाद्य श्रीर बिजली के पंखे, उत्पादन की मात्रा को कम होने से रोकने की वृट्टि से सर्वसाधारण के हित में ऐसा करना आवश्यक है;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 18चब की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि—

- (क) इस आदेश की अनुसूची में विनिर्दिष्ट, यथास्थिति, प्रधिनियमितियां या उनका कोई भाग उक्त श्रीधोगिक उपक्रम को लागू नहीं होगा, और
- (ख) सभी प्रवृत्त सर्विदाओं, संपत्ति का हस्तान्तरणपन्नों, करारों, समझौतों, पंचाईं, स्थायी आदेशों या अन्य लिखतों (बैंकों को और वित्तीय संस्थानों को प्रतिभूत दायित्व से संबंधित को छोड़कर), जिनमें उक्त श्रीधोगिक उपक्रम पक्षकार हैं या

जो द्वादश आदेश के गजपत्र में प्रकाशन की तारीख से ठीक पूर्व लागू होती हों, का प्रबल्लन और सभी अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यताएं और वायित्व को उक्त तारीख से पहले तद्धीन प्रोद्भूत या उद्भूत हुए हों निलम्बित रहेंगे।

2. यह आदेश राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रारम्भ होकर एक वर्ष की अवधि के लिए प्रदृश रहेगा।

अनुसूची

1. श्रीधोगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946।
2. श्रीधोगिक विवाद अधिनियम, 1947 के निम्नलिखित अध्याय और धाराएं, अर्थात् :—
 - (1) अध्याय 5—क।
 - (2) धारा 33(ग)।
 - (3) धारा 9(क)।

[सं० फा० 4/12/72—सी०य० सी०]

के० एस० भटनागर, संयुक्त सचिव।

